

The Statesman 24-June-2021

Monsoon likely to elude Delhi till end of June: IMD



Pigeons take bath at a water sprinkler on a hot day, in the Capital on Wednesday.

SUBRATA DUTTA

PTI

NEW DELHI, 23 JUNE

Delhi is unlikely to receive monsoonal showers till the end of June and the maximum temperature in the city is predicted to hover around 40 degrees Celsius till then, according to the India Meteorological Department.

On Wednesday morning, the national capital recorded a minimum temperature of 28 degrees Celsius, normal for this time of the year. The maximum temperature is likely to settle around 39 degrees Celsius, the MeT office said.

After reaching Kerala two days late, monsoon raced across the

country, covering eastern, central and northwest India seven to 10 days ahead of schedule, according to the IMD.

However, further progress over the remaining parts of the country, including Delhi, parts of Rajasthan, Haryana and Punjab, is unlikely during the next seven days, the IMD said on Tuesday.

Kuldeep Srivastava, the head of the IMD's regional forecasting centre, said light rains are likely in Delhi-NCR around June 26 but the region will have to wait more for monsoonal showers.

The MeT office had earlier predicted that the wind system may reach Delhi by June 15, 12 days ahead

of schedule.

Normally, monsoon reaches Delhi by June 27 and covers the entire country by July 8.

Last year, the wind system reached Delhi on June 25 and covered the entire country by June 29, according to Skymet Weather, a private forecasting agency.

Mahesh Palawat from Skymet Weather said chances are that Delhi will receive monsoonal showers only around the end of June.

"Westerly winds have been blocking the advance of the monsoon into the remaining parts of northwest India for some days. These are expected to persist for at least one week," he said.

New Indian Express 24-June-2021

UNDUE DELAYS IN KRISHNA DISPUTE

Krishna waters are yet again inflaming passions between Telangana and Andhra Pradesh. Contending that AP is going ahead with its “illegal project” of Rayalaseema Lift Irrigation Scheme drawing water from the Srisailem reservoir on the border despite the NGT’s restraining order, the Telangana Cabinet has cleared the construction of many new projects on the river, including a barrage between Gadwal and Wanaparthy to impound 55.3 tmcft water; Pulichintala left canal and a lift irrigation scheme at Sunkesula. The AP government has slammed Telangana saying all of them were “illegal projects”. The row is snowballing into a high-octane political drama.

Telangana has been demanding a share of 550 tmcft of the total 811 tmcft that the Bachawat Tribunal had allotted for the erstwhile undivided Andhra Pradesh. The tussle for a fair share of Krishna waters between the two states has only been intensifying ever since bifurcation in 2014. Telangana argues that since one of the cornerstones of the movement for a separate state was ensuring justice to its people in share of river waters, it cannot compromise on it. Demanding a fresh review of its share, Telangana has asked the Centre to appoint a new tribunal and, on its direction, has even withdrawn its case in the Supreme Court but so far nothing has happened. As the Brijesh Kumar Tribunal’s award, pronounced in 2010, is in a state of limbo since the issue is in the Supreme Court, the time-worn Bachawat Tribunal’s award applies even today about which neither state is happy. Resolving the labyrinth of issues involved may look daunting, but this should not be the reason for the apex council to abdicate its responsibility of ensuring an amicable settlement between the two states. It was in 2004 that the Brijesh Kumar Tribunal was constituted (it gave its award in 2010 for 1,004 tmcft water for undivided AP). This means the issue has been hanging fire for 17 years.

While the states may prefer courtroom battles, they need to come to the negotiating table and settle the issue amicably. The irritants could be hammered out if the Centre takes a sincere apolitical approach, but unfortunately it hasn’t. The undue delays at various fora like the apex court, tribunals and apex council in resolving the issues between the warring states are unacceptable.

Hindustan 24-June-2021

नजरिया

उपेक्षा का दंश झेलती हरी हो रही हमारी नदियां

लखनऊ में गोमती व बनारस में गंगा जल के हरे होने की वजह प्रदूषण है। इन नदियों से जलीय जीव-जंतु खत्म होने लगे हैं।

अंबरीश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार



समाजवादी चिंतक डॉ राम मनोहर लोहिया एक यात्रा के दौरान दक्षिण भारत की एक नदी में स्नान कर रहे थे। वहां मौजूद एक मछुआरे ने उनसे पूछा, 'आपका मुलुक किस नदी के किनारे है?' अचानक पूछे गए इस सवाल से लोहिया कुछ देर के लिए तो हैरान रह गए। लेकिन फिर जवाब दिया, 'मैं सरयू का पुत्र हूँ।' मछुआरे ने मुस्कराकर उनसे कहा, 'अच्छा, तो राजा रामचंद्र के गांव के हो।' इस घटना का जिक्र लोहिया ने अपनी एक टिप्पणी में किया था। इस प्रसंग से पता चलता है कि नदियों से लोगों का क्या रिश्ता होता था। नदियों के किनारे ही विश्व की ज्यादातर सभ्यताएं विकसित हुईं, लेकिन पिछले चार-पांच दशकों में ही नदियों का क्या हाल हो गया, इसके दो उदाहरण का जिक्र मैं यहां करूंगा।

पहला उदाहरण गोमती नदी है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब हरी-हरी दिखने लगी, तब यहां के लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पर हरी होती गोमती के बहुत से चित्र दिखाई पड़े। असल में, आदि गंगा मानी जाने वाली गोमती के पानी पर इतनी ज्यादा जलकुंभी हो गई थी कि कहीं पानी दिख ही नहीं रहा था। हालांकि, गोमती में जब जलकुंभी नहीं थी, तब भी इसका पानी नहाने लायक तक नहीं बचा था। एक कड़वा सच यह भी है कि लखनऊ में इस नदी की मछली वर्षों से कोई नहीं खाता, क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। लखनऊ में घाघरा नदी से पकड़ी गई मछलियां बिकती हैं या फिर माताटीला ताल से लेकर आसपास के ताल-तालाब की मछलियां आती हैं। आंध्र प्रदेश से भी मछली यहां आती है, तो समुद्र की भी। लेकिन शहर के बीचोबीच बहने वाली गोमती की मछली लखनऊ में नहीं मिलेगी। कुछ यही हाल गुजरात की दमन गंगा नदी का भी है, जिसका पानी इतना दूषित हो चुका है कि वहां से मछली एक दशक पहले ही गायब हो चुकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अब देश की कई अन्य नदियां भी इसी दिशा में जा रही हैं।

बहरहाल, जलकुंभी गोमती नदी की बदहाली का संकेत और संदेश, दोनों दे रही है। जलकुंभी के छाने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इनमें पलने वाली मछलियों के साथ-साथ अन्य जलीय जीव और वनस्पतियां दम तोड़ने लगती हैं। यही नहीं, जलकुंभी पानी के बहाव को भी 20 से 40 फीसदी तक कम कर देती है, जिससे नदी का पानी एक तरह से ठहर जाता है।

और, अगर चलता हुआ पानी ठहर जाए, तो वह किसी काम का नहीं रहता। वैसे, गोमती का पानी लखनऊ पहुंचने से पहले ही काफी प्रदूषित हो चुका होता है। पीलीभीत से निकलने वाली इस नदी में कई चीनी मिलों और शराब के कारखानों के कचरे तो बहते ही हैं, इसमें सीवेज का नाला भी जगह-जगह पर गिराया जाता है। इसके बाद जलकुंभी के हमले से यह नदी भला कैसे बच सकती है?

दूसरा उदाहरण बनारस में बहती गंगा का है, जिसके पानी के हरे होने का कारण शैवाल था, जो बहुत ही जहरीला होता है। पानी हरा हुआ, तो स्वाभाविक ही लोगों की चिंता भी बढ़ी। गंगा प्रदूषित तो पहले से है, लेकिन पानी के हरे रंग ने लोगों की और डरा दिया। डर के साथ लोग यह जानना भी चाहते थे कि आखिर अचानक पानी हरा कैसे हो गया? हालांकि, बरसात के मौसम में ताल-तालाब के उल्टे प्रवाह के चलते गंगा में कई बार काई

अच्छे मानसून के कारण नदी-नालों का जल प्रवाह बढ़ेगा। ऐसे में, नदियों से जलकुंभी व शैवाल हटाने का काम हो सकता है।

आ जाती थी, जिससे पानी कुछ जगह हरा दिखता था, लेकिन इस बार यह हरापन शैवाल की वजह से हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कहीं पानी स्थिर हो जाता है, तब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसमें माइक्रोसिस्टिस पनपता है। यह आमतौर पर नाले और तालाब में पाया जाता है। ऐसा लगता है कि यह वहाँ से बहकर आया। इसे यदि साफ नहीं किया गया, तो यह जलीय जीव-जंतुओं को खत्म कर देगा। इसलिए इसे जल्द से जल्द हटाना चाहिए।

इन नदी क्षेत्रों में बरसात का मौसम आ चुका है। इसे नदियों के नहाने का मौसम भी कहते हैं। दरअसल, इसका कारण यह है कि अच्छे मानसून की वजह से नदी-नालों का जल प्रवाह बढ़ जाता है। अगले दस-पंद्रह दिनों में अपने यहां यह स्थिति आने वाली है। ऐसे में, चाहे जलकुंभी हो या शैवाल, इन्हें हटाने का काम ज्यादा आसानी से किया जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

India Today 24-June-2021

सुर्खियां

उत्तराखंड

भू-गर्भ में छुपा जल खजाना

अखिलेश पांडे

पर्यटकों की मुख्य आकर्षण रही झील नगरी नैनीताल की नैनी झील के मुहाने से लगभग 400 मीटर दूर जमीन के नीचे करीब

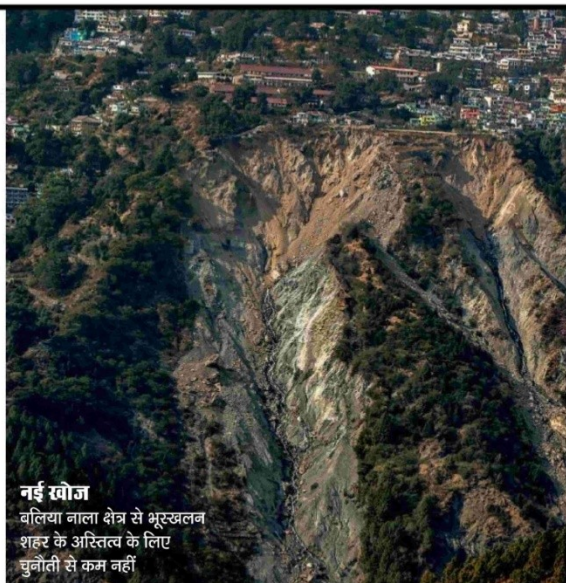
200 मीटर लंबी और पांच मीटर तक गहरी झील होने का पता लगा, जिसे अधिकारी इस नगरी की रक्षा के लिए दैवीय वरदान से कम नहीं मान रहे हैं। आइआइटी रुड़की के भू-भौतिकी विभाग के प्रोफेसर आनंद जोशी और प्रोफेसर संदीप सिंह की उत्तराखंड सिंचाई विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, बलिया नाला क्षेत्र में पानी रिसाव का कारण बने जलस्रोतों के समीपवर्ती 70 मीटर इलाके के भूमिगत भू-भौतिकी सर्वे में यह झील दिखाई है। मजे की बात यह भी है कि बलिया नाला इलाके में यह भूमिगत झील नैनीझील से नहीं जुड़ी है।

नैनी झील के रख-रखाव से जुड़े सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश चंद्र सिंह के अनुसार इसका सीधा मतलब यह है कि इस भूमिगत झील का पानी निकाला जाए तो नैनी झील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भूमिगत झील के मिलने से प्रशासन और नैनीताल की बलिया नाले वाली तलहटी के भूस्खलन से परेशान निर्माण एजेंसियों को भी राहत महसूस हुई है। सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि पानी का रिसाव नैनी झील से नहीं, बल्कि भूमिगत झील से हो रहा है।

बलिया नाला क्षेत्र में 2014 और 2018 में हुए भूस्खलन से पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा था। कई घरों को खाली करवाना पड़ा था। शहीद मेजर राजेश अधिकारी इंटर कॉलेज भी भूस्खलन की चपेट में आया था। 100 साल पुराने इस स्कूल को शिफ्ट करने की नौबत आई तो सिंचाई विभाग ने रुड़की स्थित नेशनल हाइड्रोलॉजी संस्थान से इस क्षेत्र के

नई खोज

बलिया नाला क्षेत्र से भूस्खलन शहर के अस्तित्व के लिए चुनौती से कम नहीं



अमित साह

तमाम जलस्रोतों का आइसोटोपिक परीक्षण करने का जिम्मा सौंपा, ताकि पता चले कि पानी का रिसाव नैनी झील से हो रहा है या कोई और स्रोत है। पता चला रिसाव नैनी झील से नहीं हो रहा है।

उसकी रिपोर्ट के बाद हाइकोर्ट के आदेश से समस्याग्रस्त बलिया नाला क्षेत्र के सर्वे के लिए आइआइटी रुड़की, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट, जीएसआइ समेत कई एजेंसियों की कमेटी बनाई गई। आइआइटी रुड़की की सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि पानी का रिसाव नैनीझील से नहीं बल्कि भूमिगत झील से हो रहा है। आइआइटी रुड़की की सर्वे रिपोर्ट ने साफ किया कि जीजीआइसी से सिपाही धारा तक लगभग 200 मीटर की लंबाई में पानी का भूमिगत स्रोत है, जो झील की तरह है, जिससे बलिया नाला में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर पानी निकल रहा है, जो नैनीताल शहर के कुल पेयजल आवश्यकता के बराबर है।

इस खुलासे के बाद नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्र्याल ने पानी लिफ्टिंग के लिए गठित कमेटी के सदस्यों को पानी की उपलब्धता जांचने के लिए चिन्हित क्षेत्र में दो से तीन स्थानों पर बोरिंग करने के निर्देश दिए हैं। गब्र्याल कहते हैं, “इस मामले में भूगर्भ वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। हम भूमिगत पानी निकालने में सफल रहे तो नगर में पेयजल की आपूर्ति के लिए नैनीताल झील पर आश्रित नहीं रहना होगा और उसके गिरते जलस्तर

को बचाया जा सकेगा। इससे बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने में भी मदद मिलेगी।” बलिया नाले में 1980 में भूस्खलन के बाद उसके ट्रीटमेंट और सर्वे का काम शुरू हुआ। लेकिन बलिया नाले में प्रवाहित स्रोतों के पानी के प्रवाह के चलते ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिल रही थी। अब यह साफ हो गया है कि जल प्रवाह भूमिगत झील के चलते है तो उसके ट्रीटमेंट की राह भी आसान दिखने लगी है।

जिलाधिकारी ने सिंचाई और नलकूप, जल निगम वगैरह विभागों की आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो इस क्षेत्र में ट्यूबवेल स्थापित करेगी। गब्र्याल ने बताया कि इस भूमिगत पानी को अपलिफ्ट कर नैनीताल तक पहुंचाया जाएगा। अगर यह प्रयास सफल हुआ तो प्रति वर्ष ग्रीष्मकाल में नैनी झील के कम होते जलस्तर से उसके सौंदर्य को लगने वाले ग्रहण से बचाया जा सकेगा और शहरवासियों को पेयजल किल्लत और अमूमन प्रदूषित पेयजल से लगने वाली बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा।

खुशखबरी यह भी है कि भूमिगत झील के चलते प्रवाहित हो रहे बलिया नाला क्षेत्र के जल को नेशनल हाइड्रोलॉजिकल सर्वे संस्थान गुणवत्ता में नैनी झील से अधिक बढ़िया और प्रदूषण मुक्त पानी पा चुका है। देवभूमि को यकीनन यह दैवी वरदान है। इन स्रोतों के उचित दोहन से न केवल नैनीताल की प्यास बुझेगी बल्कि भूस्खलन का बचाव कार्य भी संभव हो जाएगा। ■